



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 2 अगस्त, 2010/11 श्रावण, 1932

हिमाचल प्रदेश सरकार

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 31 जुलाई, 2010

संख्या पी.बी.डब्ल्यू. (बी) एफ (5) 67/2010.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव मटयारा/556, तहसील बल्दाडा, जिला मण्डी में जोगिन्द्रनगर-सरकाघाट-घुमारव सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी, हिमाचल प्रदेश के समक्ष लिखित आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	उप-तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र है० में
मण्डी	बल्दाड़ा	मटयारा/556	485/1	0-00-48
			477/1	0-02-33
			659/470/1	0-01-72
			652/324/1	0-01-30
			405/1	0-00-52
			401/1	0-00-33
			400/1	0-00-36
			694/393/1	0-00-88
			344/1	0-02-49
			कुल जोड़ किता-9	0-10-41

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
प्रधान सचिव।

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 31 जुलाई, 2010

सं० पी०बी०डब्ल्यू० (बी०) एफ-5) 114/2009.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव कुन प्लेट, तहसील नालागढ़, जिला सोलन में पिन्जौर-नालागढ़-स्वारघाट राष्ट्रीय उच्च मार्ग-21 ए को चौड़ा करने हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र बीघा-बिस्वा
सोलन	नालागढ़	कुन प्लेट	289/243/1	0-16
			269/1	1-10
			239/2/1	0-2
			250/1	0-5
			417/249/1	0-10
			238/2/1	2-6
			445/418/249/1	0-4
			433/235/2/1	0-15
			425/234/2/1	0-16
			320/229/1	0-3
			246/1	0-16
			248/2/1	0-4
			248/1/1	0-3
			447/236/1	0-7
			433/235/2/1	0-15
कुल जोड़ किता- 15				9-12

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित /—
प्रधान सचिव।

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 31 जुलाई, 2010

सं० पी०बी०डब्ल्यू० (बी०) एफ-5) 118/2009.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव जगतपुर, तहसील नालागढ़, जिला सोलन में पिन्जौर-नालागढ़-स्वारघाट राष्ट्रीय उच्च मार्ग-21 ए को चौड़ा करने हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र बीघा-बिस्वा
सोलन	नालागढ़	जगतपुर	530 / 401 / 120 / 1	3-8
			55	0-7
			56	0-6
			118 / 1	0-4
			117 / 1	0-4
			116 / 1	0-2
			115 / 1	0-4
			114 / 1	0-4
			113 / 1	0-6
			404 / 120	0-8
			121 / 1	0-7
			455 / 124 / 1	0-3
			456 / 124 / 1	0-7
			409 / 137 / 1	0-9
			125 / 1	0-2
			126 / 1	0-6
			136 / 1	0-4
			138 / 1	0-4
			531 / 408 / 137	0-4
		कुल जोड़ किता-19		7-19

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / -
प्रधान सचिव।

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 31 जुलाई, 2010

संख्या पी.बी.डब्ल्यू. (बी) एफ (5)13/2010.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव फाटी भ्यार, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में सड़क लुहरी ओट स्थित खुन्दन पुल के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी, हिमाचल प्रदेश के समक्ष लिखित आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र है० में
कुल्लू	बन्जार	फाटी भ्यार	1596 / 1	0-2-8
			1594 / 1	0-5-07
		कुल जोड़ किता-2		0-7-15

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / -
प्रधान सचिव।

विधि विभाग

शुद्धि पत्र

शिमला-2, 2 अगस्त, 2010

संख्या एल०एल०आर०-ई(९)-18/2005-लेज.—इस विभाग के सम संख्यांक अधिसूचना दिनांक 22 जुलाई, 2010 जो कि राजपत्र हिमाचल प्रदेश में दिनांक 24 जुलाई, 2010 को पृष्ठ संख्या 2349 में प्रकाशित हुआ है, में “अरविन्द शर्मा” शब्द जहां कहीं भी आये हों को “अरविन्द धिमान” शब्द पढ़ा जाए।

आदेश द्वारा,
अवतार चन्द डोगरा,
सचिव (विधि)।

[Authoritative English Text of this Department Notification No. LLRE(9)18/2005-Leg. Dated 02-08-2010 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

LAW DEPARTMENT

CORRIGENDUM

Shimla-2, the 2nd August, 2010

No. LLR-E(9)-18/2005-Leg. In Authoritative English Text of this Department Notification of even number dated 22-07-2010, published in Rajpatra, Himachal Pradesh on 24-07-2010 at page 2349, for the words “Arvind Sharma” wherever these occur, the words “Arvind Dhiman” may be read.

By order,
AVTAR CHAND DOGRA,
LR-cum-Secretary (Law).

DEPARTMENT OF TOURISM & CIVIL AVIATION**NOTIFICATION***Shimla-171002, the 31st July, 2010*

No. TSM-A(8)-1/2010.—In supersession of this department's notification No.TSM-E(3)-5/2007 dated 7.07.2009, the Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred under clause 1 & 2 of Section 5 and clause 1 of Section 19 of the Right to Information Act, 2005 (Act No. 22 of 2005), is pleased to appoint/nominate the following officers for the implementation of Right to Information Act, 2005 in respect of Tourism & Civil Aviation Department:-

Sr. No.	Designation	Office Address	Office telephone No.	E-mail address	Jurisdiction	Nominated as
1.	Principal Secretary (Tourism & Civil Aviation) to the Government of Himachal Pradesh.	Armsdale Building, H.P.Sectt. Shimla-171002.	0177-2621195	Tourismsecyhp@ nic.in	Administrative Deptt. level in the Secretariat in respect of Tourism & Civil Aviation Section.	Appellate Authority
2.	Special/Additional/Joint/Deputy/Under Secretary (Tourism) to the Govt. of H.P.	Armsdale Building, H.P.Sectt. Shimla-171002.	0177-2628475	---	Administrative Deptt. level in the Secretariat in respect of Tourism & Civil Aviation Section.	Public Information Officer
3.	Section Officer, Tourism & Civil Aviation Section, H.P. Sectt. Shimla.	Armsdale Building, H.P.Sectt. Shimla-171002.	0177-2880573	---	Administrative Deptt. level in the Secretariat in respect of Tourism & Civil Aviation Section.	Assistant Public Information Officer

By Order,
MANISHA NANDA,
Principal Secretary (Tourism & Civil Aviation).

DEPARTMENT OF TOURISM & CIVIL AVIATION**NOTIFICATION***Shimla-171002, the 31st July, 2010*

No. TSM-A(8)-1/2010.—In supersession of this Department's Notification No.TSM-E(3)-5/2007 dated 7.07.2009, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to publish the records and other activities of the Tourism & Civil Aviation Department at Administrative Department level at Secretariat as required under the provisions of Sub Section (1) (b) of Section 4 of the Right to Information Act, 2005 as under:—

(i) THE PARTICULARS OF ITS ORGANISATION, FUNCTIONS AND DUTIES;

Chief Minister is the Minister-in-charge of Tourism & Civil Aviation Department and the organization setup of the Department is as under:—

GOVERNMENT/SECRETARIAT LEVEL

1. Principal Secretary (Tourism & Civil Aviation) to the Government of Himachal Pradesh.
2. Special/Additional/Joint/Deputy/Under Secretary to the Government of Himachal Pradesh (as the case may be).
3. Section Officer as Section Incharge.
4. Superintendent.
5. Senior Assistants.
6. Junior Assistants.
7. Clerks.
8. Personal Staff i.e. Private Secretary/Personal Assistants/ Sr.& Jr. Scale Stenographers/Steno-typists.
9. Peons.

FUNCTION AND DUTIES:-

At Secretariat level the Tourism & Civil Aviation Department has one section. Principal Secretary (Tourism & Civil Aviation) is the administrative head of the Department and discharges the following duties of the Department:-

1. Development and promotion of Tourism.
2. State and District Tourist Advisory Committees.
3. Tourist Services- Supply of information, reservation of accommodation and provision of other amenities.
4. Hotel Legislation.
5. Construction/maintenance of departmental tourist accommodation.
6. Sports such as Aero Sports, Adventure Sports, Winter Sports, Golf, Boat Clubs, Mountain biking, River rafting etc.
7. Recognition of Travel agents and Shikar agents.
8. Matters relating to shooting of films in Himachal Pradesh.
9. Establishment, budget and accounts matters.
10. Fossil Park and Food Craft Institute.
11. Development of lakes in Himachal Pradesh.

12. Civil Aviation and Flying Clubs including Flying Training, Aero Sports Institute, Hang Gliding, Para Gliding Training and competitions, Site selection for airstrips, Helicopter services, Air-craft operations, upgrading of helipads and upgrading/extension of airports.
13. Establishment of ropeways.
14. Appeals relating to Essentiality Certificates.

This Department is administrative Department in reference to H.P. Tourism Development Corporation.

(ii) THE POWERS AND DUTIES OF ITS OFFICERS AND EMPLOYEES;

Principal Secretary (Tourism & Civil Aviation) to the Govt. of H.P:-

Principal Secretary is the head of the Department and maintains overall control of the Department.

Special/Additional/Joint/Deputy/Under Secretary (Tourism):-

To assist the Principal Secretary (Tourism) on the issues as stated above.

Section Officer:-

The Section Officer is the in charge of the section. He/she performs following duties:-

1. Supervise all the work of section and marking dak to the Assistants.
2. Ensure timely submission of time bound cases/court cases.
3. Ensure all the Dealing Asstts. And Diarist are maintaining al required registers and keep the same updated.
4. To keep carefully watch on the movements of dak /files between section and higher authorities.

Superintendent Gr-II:-

Superintendents Grade-II working in the Secretariat supervises work of the dealing assistants posted in the Section and submits their cases through the Section Officers. In the absence of Section Officer, the Superintendent Grade-II supervises the work of entire Section.

Senior/Junior Assistants:-

Senior/Junior Assistants deal with receipts and submit cases to the Section Officer through Superintendent. They are required to compile data or information and deal with matters including Cabinet Memorandums/Court Cases/Replies of Vidhan Sabha Question, so as to present complete cases with all relevant data and information with past precedents and viable/ feasible solutions to facilitate the authorities to arrive at a definite decision. They are also required to maintain record/registers.

Clerks:-

Clerks posted in the Section perform duties and functions as assigned to them by the Section Officer/Superintendent including the Diary/Dispatch work, maintain casual leave account, distribute dak after dairying to dealing assistants in the Section and open new files.

Personal Staff: -

The general function of Personal staff *i.e.* Private Secretary/Personal Assistant/Senior and Junior Scale Stenographers/Steno Typists is to assist the Minister, Secretary and other Middle level Officers in their day-to-day disposal of work and carry out such duties officially assigned to them. They have to handle files/records of confidential or secret nature and as such they have to retain the faith reposed in them by maintaining secrecy. They are also supposed to be fully equipped with knowledge of both Hindi and English shorthand and typewriting to assist the authorities in quick decision-making through dictation and typing. Further they have to perform the duties of Receipt of dak, preparation of notes and drafts. Attendance of telephones, Maintenance of Engagement Diary, Control over Vehicle/Driver, Arrangements for tours/pay etc., and also for maintenance of records.

(iii) THE PROCEDURE FOLLOWED IN THE DECISION MAKING PROCESS, INCLUDING CHANNELS OF SUPERVISION AND ACCOUNTABILITY;

All the cases received in Tourism Section are submitted on files by the concerned dealing assistants, supervised by the Superintendent and submitted to the Section Officer. He submits it further to the Under/Deputy/Joint/Addl./Special Secretary and then to the Principal Secretary. Routine matters and informatory references are disposed of at Under/Deputy/Joint/Addl./Special Secretary level.

(iv) THE NORMS SET BY IT FOR THE DISCHARGE OF ITS FUNCTIONS;

As stated at point (iii) above.

(v) THE RULES, REGULATIONS, INSTRUCTIONS MANUALS & RECORDS HELD BY IT OR UNDER ITS CONTROL OR USED BY ITS EMPLOYEES FOR DISCHARGING ITS FUNCTIONS;

The following various rules, regulations, instructions are followed while functioning the different works:—

- Rules of Business of Govt. of H.P.
- Standing Orders issued by Tourism Deptt.
- RTI Act, 2005 and Rules framed thereunder.
- Office Manual.
- CCS (conduct) Rules, 1964.
- CCS (Leave) Rules, 1972.
- CCS (CC&A) Rules, 1965.
- TA/LTC Rules.
- GPF Rules.
- H.P. Financial Rules.
- CCS (Pension) Rules, 1972.
- FR & SR.
- H.P. Tourism Development & Registration Act & various rules framed thereunder.
- Handbooks Volume-I, II & III on personnel issued by the Department of Personnel.
- Vigilance Manual.
- Instructions regarding maintenance of ACRs. Instructions regarding pay fixation, Stepping up of pay, granting of ACPS benefits and removal of anomaly in pay of senior and junior officers and other relevant instructions issued by the advisory departments from time to time.
- Guidelines/parameters relating to Essentiality Certificate/Ropeways.

- HP Aero Sports Rules/HP River Rafting Rules.

(vi) A STATEMENT OF THE CATEGORIES OF THE DOCUMENTS THAT ARE HELD BY IT OR UNDER ITS CONTROL;

Personal files of Class-I & -II Officers, all files relating to service/establishment matters of all categories of employees and other files relating to subject matters of Tourism Department.

(vii) THE PARTICULARS OF ANY ARRANGEMENT THAT EXISTS FOR CONSULTATION WITH, OR REPRESENTATION BY, THE MEMBERS OF THE PUBLIC IN RELATION TO THE FORMULATION OF ITS POLICY OR IMPLEMENTATION THEREOF;

The policy formulation matters are sent to the cabinet for decision in consultation with advisory Departments *i.e.* DOP, Finance and Law HP and HP Public Service Commission (if needed be).

(viii) A STATEMENT OF THE BOARDS, COUNCILS, COMMITTEES AND OTHER BODIES CONSISTING OF TWO OR MORE PERSONS CONSTITUTED AS ITS PART OR FOR THE PURPOSE OF ITS ADVICE, AND AS TO WHETHER MEETINGS OF THOSE BOARDS, COUNCILS, COMMITTEES AND OTHER BODIES ARE OPEN TO THE PUBLIC, OR THE MINUTES OF SUCH MEETINGS ARE ACCESSIBLE FOR PUBLIC;

A Tourism Development Board under the chairmanship of Hon'ble Chief Minister has been constituted. Tourism Councils for Manali has also been constituted for the development of tourism. The minutes of the Board/Council are accessible for public.

(ix) A DIRECTORY OF ITS OFFICERS AND EMPLOYEES;

Principal Secretary (Tourism & Civil Aviation) to the Govt. of H.P.	Ph. No. 0177-2621195
Joint Secretary (Tourism) to the Govt. of H.P.	Ph. No. 0177-2628475
Section Officer, Tourism Section	Ph. No.0177-2880573
Supdt. Tourism Section	Ph. No. 0177-2880573

(x) THE MONTHLY REMUNERATION RECEIVED BY EACH OF ITS OFFICERS AND EMPLOYEES, INCLUDING THE SYSTEM OF COMPENSATION AS PROVIDED IN ITS REGULATIONS;

1.	Pr. Secretary (Tourism)	=	Pay Band of Rs. 37,400-67,000/- with Grade Pay of Rs. 10,000/-.
2.	Joint Secretary (Tourism)	=	Pay Band of Rs. 15,600-39,100/- with Grade Pay of Rs. 7600/-.
3.	Section Officer/Private Secretary	=	Pay Band of Rs. 10300-34800/- with Grade Pay of Rs.5,000/-
4.	Supdt./P.A.	=	Pay Band of Rs. 10300-34800/- with Grade Pay of Rs. 4,200/-
5.	Sr. Assistant/Sr. Scale Steno.	=	Pay Band of Rs. 10300-34800/- with Grade Pay of Rs. 3,800/-

6.	Jr. Asstt./Jr. Scale Steno.	=	Pay Band of Rs. 5910-20200/- with Grade Pay of Rs. 2800/-
7.	Clerk	=	Pay Band of Rs. 5910-20200/- with Grade Pay of Rs. 1900/-
8.	Peon	=	Pay Band of Rs. 4900-10680/- with Grade Pay of Rs. 1300/-

No compensation is being provided to the officers/officials.

- (xi) THE BUDGET ALLOCATED TO EACH OF ITS AGENCY, INDICATING THE PARTICULARS OF ALL PLANS, PROPOSED EXPENDITURES AND REPORTS ON DISBURSEMENTS MADE; N.A.
- (xii) THE MANNER OF EXECUTION OF SUBSIDY PROGRAMMES, INCLUDING THE AMOUNTS ALLOCATED AND THE DETAILS OF BENEFICIARIES OF SUCH PROGRAMMES; N.A.
- (xiii) PARTICULARS OF RECIPIENTS OF CONCESSIONS, PERMITS OR AUTHORIZATIONS GRANTED BY IT; N.A.
- (xiv) DETAILS IN RESPECT OF THE INFORMATION, AVAILABLE TO OR HELD BY IT, REDUCED IN AN ELECTRONIC FORM;
At Secretariat level only Refnic system is available.
- (xv) THE PARTICULARS OF FACILITIES AVAILABLE TO CITIZENS FOR OBTAINING INFORMATION, INCLUDING THE WORKING HOURS OF A LIBRARY OR READING ROOM, IF MAINTAINED FOR PUBLIC USE;

The office of the Principal Secretary (Tourism) to the Govt. of H.P. and other offices of this department are open for general public for collection of any type of information from 10 AM to 5 PM on every working day. To visit the offices as well as section, the gate entry passes are issued to the general public from 3 PM to 5 PM on every working day by the Secretariat Administration (Reception Section).

- (xvi) The names, designations and other particulars of the Public Information Officers;

Name and Designation	Office Address	Office telephone No.	E-mail address	Jurisdiction
Smt. Ameeta Mahajan, Joint Secretary (Tourism) to the Govt. of H.P.	Armsdale Building, H.P.Sectt. Shimla-171002.	0177-2628475		Administrative Deptt. level in the Secretariat in respect of Tourism & Civil Aviation Section.

- (xvii) SUCH OTHER INFORMATION AS MAY BE PRESCRIBED; Nil.

By order,
MANISHA NANDA,
Pr. Secy. (Tourism & Civil Aviation).

परिवहन विभाग**अधिसूचना**

शिमला-2, 30 जुलाई, 2010

संख्या टी.पी.टी.-एफ (6)-2/2000.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1998 का 59) की धारा 212 के साथ पठित धारा 211 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्या 5-24/88-टी.पी.टी.-11, तारीख 12 जुलाई, 1999 द्वारा राजपत्र हिमाचल प्रदेश (असाधारण), तारीख 27 जुलाई, 1999 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1999 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने का प्रस्ताव करती है और उन्हें जनसाधारण की सूचना के लिए राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ;

2. इस नियमों द्वारा संभाव्य होने वाले किसी व्यक्ति को, यदि इन नियमों की बाबत, कोई आक्षेप या सुझाव करने हैं, तो वह उसे/उन्हें प्रधान सचिव (परिवहन), हिमाचल प्रदेश सरकार, आर्मजडेल भवन, शिमला -2 को उपरोक्त प्रारूप नियमों के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से, तीस दिन की अवधि के भीतर भेज सकेगा :

3. नियत अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेपों या सुझावों, यदि कोई हों, पर उक्त प्रारूप नियम को अंतिम रूप देने से पूर्व, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा विचार किया जाएगा, अर्थात् :-

प्रारूप नियम

1. **संक्षिप्त नाम.**—इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मोटर यान (तृतीय संशोधन) नियम, 2010 है ।

2. **नियम 69-ख का प्रतिस्थापना.**—हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1999 के विद्यमान नियम 69-ख के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“69-ख, रजिस्ट्रीकरण नम्बर (चिन्ह) के आबंटन के लिये विशेष रजिस्ट्रीकरण फीस.—हिमाचल प्रदेश राज्य में, समस्त रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन प्राधिकारियों द्वारा केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 81 के अधीन मोटरयानों के लिए निम्नलिखित रजिस्ट्रीकरण नम्बरों (चिन्हों) के आबंटन के लिए रजिस्ट्रीकरण फीस के अतिरिक्त, निम्नलिखित दरों पर विशेष रजिस्ट्रीकरण फीस प्रभारित की जाएगी :-

क्र० सं	रजिस्ट्रीकरण चिन्ह	विशेष रजिस्ट्रीकरण फीस
1.	0001	75,000 /रुपए (पचहत्तर हजार रुपए)
2.	0002 से 0009	50,000 /रुपए (पचास हजार रुपए)
3.	0010 से 0100	35,000 /रुपए (पैंतीस हजार रुपए)
4.	0101 से 9999	20,000 /रुपए (बीस हजार रुपए)

परन्तु कम संख्या 1 से 3 के सामने विनिर्दिष्ट विशेष रजिस्ट्रीकरण नम्बर (चिन्ह) पूर्णतः समादत्त नम्बर होंगे, और पहले आओ पहले पाओ, के आधार पर आबंटित किए जाएंगे। तथापि, जहां किसी विशिष्ट नम्बर के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, वहां उसे लॉटरी के द्वारा आबंटित किया जाएगा :

परन्तु यह और कि रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी उपयोग न किए गए नम्बरों को राज्य सरकार के स्वामित्व वाले यानों को विशेष रजिस्ट्रीकरण फीस प्रभारित किए बिना आबंटित कर सकेगा :

परन्तु यह और कि कम संख्या 4 के सामने विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण नम्बर की दशा में विशेष रजिस्ट्रीकरण फीस, केवल तभी प्रभारित की जाएगी यदि मोटर यान के स्वामी द्वारा कम संख्या 4 के सामने

विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण नम्बर में से किसी विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण नम्बर के लिए चयन उपदर्शित किया जाता है, ऐसा न होने पर ये चिन्ह क्रमानुसार/कालानुक्रम में, पहले आओ, के आधार पर आबंटित किए जाएंगे। क्रम संख्या 4 के सामने विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण नम्बर के प्रयोजन के लिए क्रमानुसार/कालानुक्रम रजिस्ट्रीकरण नम्बर 0101 से आगे प्रारम्भ होंगे:—

परन्तु यह और कि यदि कोई मोटर यान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और बीमा कम्पनी द्वारा सम्यक, रूप से पूर्ण क्षति प्रमाणित की जाती है, तो उक्त मोटर यान के स्वामी से, नए यान हेतु उसी रजिस्ट्रीकरण नम्बर के लिए विहित विशेष फीस संदत्त करनी अपेक्षित नहीं होगी, यदि उसने बीमा कम्पनी द्वारा पूर्ण क्षति के प्रमाण-पत्र को जारी करने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर, नया यान क्रय कर लिया है :—

परन्तु यह और कि स्वामी, अपने यान के विक्रय के पश्चात केवल तभी अपने यान का रजिस्ट्रीकरण नम्बर रख सकेगा, जब विक्रीत यान को रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा नया रजिस्ट्रीकरण नम्बर पुनः आबंटित कर दिया गया हो और पहला (प्राइमरी) नम्बर इस शर्त के अध्वधीन/अभ्यर्पित कर दिया गया कि स्वामी को रजिस्ट्रीकरण नम्बर के छोड़ने/अभ्यर्पित करने की तारीख से, दो मास के भीतर, नया यान रजिस्ट्रीकृत करवाना होगा। रजिस्ट्रीकरण नम्बर को रखे रखने के लिए, पहले स्वामी से कोई विशेष रजिस्ट्रीकरण फीस प्रभारित नहीं की जाएगी।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित /—
प्रधान सचिव (परिवहन)।

[Authoritative English Text of this department notification NO. TPT-F(6)2/2000, dated 30/07/2010 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

DEPARTMENT OF TRANSPORT

NOTIFICATION

Shimla-2 the 30th July, 2010

No. TPT-F(6)2/2000.—In exercise of the powers conferred by section 211 read with section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988, (59 of 1988), the Governor, Himachal Pradesh proposes to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Motor Vehicles Rules, 1999, published in Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra Ordinary), dated 27th July, 1999 vide this department notification No: 5-24/88-TPT-II, dated 12th July, 1999 and the same are hereby published in the Rajpatra, Himachal Pradesh for information of the general public;

2. If any person, likely to be affected by these rules has any objection (s) or suggestion (s) to make with regard to these rules he may send the same to the Principal Secretary (Transport), to the Government of Himachal Pradesh, Armsdale Building, Shimla-2, within a period of thirty days from the date of publication of the said draft rules in the Rajpatra, Himachal Pradesh;

3. Objection(s) or suggestion (s), if any, received within the stipulated period, shall be considered by the Government of Himachal Pradesh before finalizing the said draft rules, namely:—

DRAFT RULE

1. Short title.—These rules may be called the Himachal Pradesh Motor Vehicles (Third Amendment) Rules, 2010.

2. Substitution of rule-69-B.—For the existing rule-69-B of the Himachal Pradesh Motor Vehicles Rules, 1999, the following shall be substituted, namely:-

“69-B-Special Registration Fee for allotment of registration marks.—There shall be charged a Special Registration Fee, in addition to the registration fee, prescribed under Rule-81 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989, for allotment of the following registration marks to the Motor Vehicles by all Registering and Licensing Authorities in the State of Himachal Pradesh, at the following rates:-

Sr.No.	Registration Mark	Special Registration Fee
1.	0001	Rs. 75,000/- (Seventy five thousand)
2.	0002 to 0009	Rs. 50,000/- (Fifty Thousand)
3.	0010 to 0100	Rs. 35,000/- (Thirty five thousand)
4.	0101 to 9999	Rs. 20,000/- (Twenty Thousand)

Provided that registration marks specified against Sr. No. 1 to 3 shall be totally paid numbers and shall be allotted on first come, first serve basis. However, where more than one application is received for a particular number, the same shall be allotted by draw of lots.

Provided further that the Registering and Licensing Authority may allot unutilized specified marks to the motor vehicles owned by the State Government without charging any special Registration Fee.

Provided further that in the case of registration marks specified against Serial number 4, Special Registration Fee shall be charged only if choice is indicated by the owner of the motor vehicle for any particular registration mark out of the registration marks specified against Serial number 4, failing which these marks shall be allotted on first come first serve basis in seriatum/chronological order. For the purpose of registration marks specified against serial number 4, the seriatum/chronological order shall start from registration marks 0101 onwards.

Provided further that in case of any motor vehicles meets with an accident and is a total loss duly certified by the Insurance Company, the owner of the said motor vehicle shall not be required to pay the special registration fee prescribed for the same registration number for a new vehicles only if he purchased the new vehicle within six month from the date of issuance of total loss certificate by the Insurance Company.

Provided further that the owner may retain the registration mark of his vehicle after the sale or scrapping of old vehicle only when the sold motor vehicle is re-assigned a new registration mark by the Registering and Licensing Authority and the primary number is vacated/surrendered subject to the condition that the owner has to get the new vehicle registered within two months from the date of surrender/vacation of the registration number. For retaining the registration mark, no special registration fee shall be charged from the primary owner.

By order,
Sd/-
Principal Secretary(Transport).